जीआइएस में अब 17 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में विभागीय स्तर पर निवेश जुटाने की होड़ में यूपीसीडा ने एक लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य हासिल कर तमाम अन्य विभागों को पीछे छोड़ दिया है। अब सरकार ने जीआइएस-23 के जरिए होने वाले निवेश के लक्ष्य को 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17 लाख करोड़ कर दिया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ में दस से 12 फरवरी 2023 तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए 83 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसी के साथ सरकार ने जीआइएस-23 के जरिए होने वाले निवेश के लक्ष्य को 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17 लाख करोड़ कर दिया है। सभी विभागों के

- **ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के निवेश लक्ष्य में किया गया संशोधन**
- **यूपीसीडा ने हासिल किए एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव**

पुराने निवेश लक्ष्यों को भी संशोधित किया गया है। इस क्रम में यूपीसीडा का निवेश लक्ष्य भी 70 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक लाख करोड़ कर दिया गया है।

यूपीसीडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मयूर माहेश्वरी ने बताया कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यस्था बनाने में पूर्ण रूप से प्रयासरत है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यूपीसीडा के वरिष्ठ अधिकारियों की नौ टीमों का गठन कर प्रथम चरण में प्रदेश के 22 जिलों में निवेशकों एवं उद्यमियों के साथ निवेश बैठकें आयोजित की गईं। गोष्ठियों में निवेशकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

इनमें मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, आटोमोबाइल, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, वेयरहाउसिंग, पेपर उद्योग, मेडिकल क्षेत्र, बायोफ्यूल, खिलौना उत्पाद, डेटा सेंटर, आइटी, इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्रों में कंपनियों ने स्थापित करने के लिए अपनी रुचि दिखाई है।

15 हजार एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार: निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए यूपीसीडा ने 15 हजार एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार कर लिया है। लाजिस्टिक एवं वेयरहाउस स्थापना के लिए वाराणसी में इंडियन कार्पोरेशन द्वारा दो हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में और भी कई निवेश हुए हैं जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 23 हजार करोड़ से अधिक, निजी औद्योगिक पार्क क्षेत्र में लगभग 21 हजार करोड़, लाजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में लगभग 10 हजार करोड़, चमड़ा और जूता उद्योग में लगभग छह हजार करोड़, गैर धात्विक और खनिज उत्पाद क्षेत्र में लगभग चार हजार करोड़ और जैव ईंधन क्षेत्र में लगभग 850 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।